



Neutral Citation No. - 2026:AHC:58715

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 1813/2026

वीरपाल चौधरी और अन्य

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

अपीलकर्ता(ओं) के अधिवक्ता

: अक्षय मिश्रा, जीशान मजहर

प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता, सुभाष चंद

न्यायालय संख्या - 51

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार-X

1. हमने अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री अक्षय मिश्रा, प्रतिवादी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री सुभाष चंद के ब्रीफ़ धारक श्री प्रमोद कुमार और राज्य के विद्वान विधि अधिकारी श्री शुभम टंडन की दलीलें सुनीं और अभिलेख का अवलोकन किया।

2. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 14-ए(1) के तहत यह आपराधिक अपील इस अपील को स्वीकार करने और दिनांक 21.02.2025 को जारी आरोपपत्र और विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम) अलीगढ़ द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 2664/2025 (वीरपाल और अन्य बनाम राज्य) में दिनांक 02.05.2025 को पारित आक्षेपित आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई है जो मुकदमा अपराध संख्या 430/2024 अंतर्गत धारा 74, 115(2), 351(2) और 352 भारतीय न्याय संहिता तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(va) पुलिस स्टेशन - छर्छा, जिला अलीगढ़ से उत्पन्न है।

3. प्रतिवादी/पीड़िता ने एफआईआर में बताया है कि 2 दिसंबर 2024 को दोपहर लगभग 12 बजे वह अपने पशुओं के लिए चारा लेने जंगल गई थी। उसने आरोप लगाया है कि उसने कुछ दूरी पर अपीलकर्ता वीरपाल चौधरी को शराब पीते देखा। जब उसने चारा बांध लिया और जाने

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



ही वाली थी कि वीरपाल पीछे से आया, उसका चारे का गट्ठा फेंक दिया, उसका हाथ पकड़ लिया और उसके साथ बदसलूकी करने लगा। जब उसने विरोध किया, तो उसने उस पर हमला किया। उसने आगे बताया है कि जब उसने शोर मचाया, तो सोनू की पत्नी रीना देवी और अन्य लोग वहां आए और उसे बचाने की कोशिश की। आरोप है कि वीरपाल ने रीना देवी पर भी हमला किया। इसी बीच, वीरपाल का भाई अपीलकर्ता लोकेश चौधरी भी मौके पर पहुंच गया। दोनों ने कथित तौर पर सूचनादाता और रीना देवी को गंदी भाषा में गालियां दीं, जातिवादी अपशब्दों का प्रयोग किया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया, साथ ही धमकी दी कि अगर उन्होंने घटना का खुलासा किसी को किया, तो वे उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को जान से मार देंगे।

4. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि एफआईआर स्वयं पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई थी; हालांकि, उसने धारा 180 और 183 बीएनएसएस के तहत अपने बयानों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि उसने कहा है कि अपीलकर्ता लोकेश उसकी ओर दौड़कर आया और उसे धक्का दिया, जो एफआईआर में नहीं कहा गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि एफआईआर में पीड़िता ने कहा है कि रीना उसकी चीखें सुनकर घटनास्थल पर पहुंची थी, और उसने विवेचनाधिकारी के समक्ष भी यही बात कही है। हालांकि, धारा 183 बीएनएसएस के तहत अपने बयान में उसने दावा किया है कि घटना के समय रीना उसके साथ मौजूद थी। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि रीना ने पीड़िता के बयान का समर्थन नहीं किया है और कहा है कि राजवती नाम की एक महिला उनकी फसलों को नष्ट करने का विरोध कर रही थी। इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि पीड़िता के बयानों में इस प्रकार की विसंगतियां अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोपों के संबंध में गंभीर संदेह पैदा करती हैं।

5. विद्वान राज्य विधि अधिकारी और सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि पीड़िता का बयान उसके साथ हुए छेड़छाड़ के संबंध में सुसंगत है। उसने बताया कि दोनों अपीलकर्ताओं ने उस पर हमला किया, गाली दी और छेड़छाड़ की। पीड़िता और गवाहों के बयानों में मामूली असंगति अभियोजन पक्ष के पक्ष को खारिज करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

6. हमने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बात सुनी और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

अस्वीकरण: “अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



7. एफआईआर स्वयं पीड़िता ने दर्ज कराई थी। एफआईआर में छेड़छाड़ का आरोप अपीलकर्ता वीरपाल पर है, और अपीलकर्ता लोकेश की भूमिका केवल इतनी है कि वह घटना के बाद आया, पीड़िता और रीना को गाली दी और उनके साथ दुर्व्यवहार किया।

8. हालांकि, बीएनएसएस की धारा 180 और 183 के तहत दिए गए अपने बयानों में पीड़िता ने अपना बयान बदल दिया है और कहा है कि अपीलकर्ता लोकेश ने भी उसके साथ मारपीट और छेड़छाड़ की थी, और उसके बाद वीरपाल आया और उसने भी इसी तरह की हरकतें कीं। यह एफआईआर में दर्ज विवरण से स्पष्ट रूप से भिन्न है।

9. रेनू के बयान से पता चलता है कि विवाद तब शुरू हुआ जब राजवती ने अपनी फसलों को हुए नुकसान पर आपत्ति जताई, जिसके बाद झगड़ा हुआ। स्वतंत्र गवाहों, अर्थात् जाहिद, दताराम, कृष्ण गोपाल और देवेंद्र ने भी कहा है कि यह घटना राजवती और जाटव समुदाय की महिलाओं, जिनमें पीड़िता भी शामिल थी, के बीच खेत की मेड़ और बाड़ को हुए नुकसान को लेकर हुए विवाद के कारण हुई थी। इन गवाहों ने छेड़छाड़ के आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि दोनों पक्षों की महिलाओं के बीच केवल झगड़ा हुआ था।

10. उपरोक्त से यह प्रतीत होता है कि घटना एक विवाद से शुरू हुई और पक्षों के बीच अचानक झगड़े में बदल गई। पीड़िता द्वारा लगाए गए आरोप अतिरंजित प्रतीत होते हैं, और उसके बयानों में स्पष्ट विसंगतियां हैं।

11. तदनुसार, यह अपील **स्वीकार** की जाती है। दिनांक 21.02.2025 का आक्षेपित आरोपपत्र और विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम), अलीगढ़ द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 2664/2025 (वीरपाल और अन्य बनाम राज्य) में दिनांक 02.05.2025 को पारित आक्षेपित आदेश, जो मुकदमा अपराध संख्या 430/2024 से उत्पन्न है, को **निरस्त** किया जाता है। फलस्वरूप, अपीलकर्ताओं के विरुद्ध उपरोक्त मामले की संपूर्ण कार्यवाही **रद्द** की जाती है।

(अनिल कुमार-X, न्यायमूर्ति)

19 मार्च, 2026

मुकेश

अस्वीकरण: “अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"